

उत्थान और पतन 2025

(Boom and Bust 2025)

वैश्विक कोयला संयंत्र पाइपलाइन पर एक नज़र

अप्रैल 2025



ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, सीआरइए, इ3जी, रिक्लेम फाइनेंस, सिएरा क्लब, एसफओसी, किको नेटवर्क, ट्रेंड एशिया, चिली सस्टेनेबिल, पोलेन ट्रांसिसिओनेस जस्टास, अरयारा, CAN Europe, WKB, DHORA, PRIED, Bankwatch, AJTN, और INSAPROMA

वैश्विक कोयला संयंत्र पाइपलाइन पर एक नजर (अप्रैल 2025)

उत्थान और पतन 2025 ([Boom & Bust Coal 2025](#)) में निम्नलिखित शीर्षक वाले खंड शामिल हैं:

(1) कार्यकारी सारांश, (2) 2024 की प्रमुख घटनाएँ, (3) वैश्विक डेटा सारांश, (4) GCPT डेटा और विश्लेषण के दस वर्ष, (5) कोयले को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने में यूके सबसे आगे, (6) निजी वित्तीय कोयला नीति प्रवृत्तियाँ, (7) चीन में एक दशक में सबसे अधिक निर्माण क्षमता शुरू, (8) भारत में एक दशक में सबसे अधिक नए कोयला संयंत्र प्रस्तावित, (9) इंडोनेशिया की कैप्टिव कोयला वृद्धि उसके न्यायसंगत परिवर्तन (जस्ट ट्रांजीशन) लक्ष्यों से अलग, (10) अमेरिका में कोयला ऊर्जा में गिरावट जारी, भले ही कुछ इकाइयाँ अभी भी चालू, (11) यूरोपीय संघ (EU27) में कोयला आधारित बिजली संयंत्र रद्द करने की दर चार गुना बढ़ी, (12) जापान और दक्षिण कोरिया कोयले के उपयोग को अमोनिया-फायरिंग के माध्यम से बढ़ाने की योजना, (13) OECD देश, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया में प्रत्येक का केवल एक नये कोयला आधारित संयंत्र बनाने का प्रस्ताव, (14) लैटिन अमेरिका में कोयला प्रस्तावों में गिरावट, लेकिन ब्राजील में सब्सिडी द्वारा इसका बचाव, (15) भारत के बाहर दक्षिण एशिया में कोयला विकास, कोयला-संबंधी ऋण के कारण घटा, (16) 2024 में इंडोनेशिया को छोड़कर दक्षिण पूर्व एशिया में कोई नया कोयला संयंत्र प्रस्तावित नहीं, (17) रूस, मध्य एशिया और मंगोलिया में वैश्विक कोयला प्रवृत्तियों का अनुसरण न कर नए कोयला संयंत्रों का निर्माण जारी, (18) पश्चिमी बाल्कन देशों में कोयला संयंत्र सेवानिवृत्ति योजनाओं और चरणबद्ध समाप्ति समय सीमा में देरी, (19) अफ्रीका में जिम्बाब्वे और जाम्बिया में कोयला ऊर्जा में वृद्धि, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में गिरावट, और (20) परिशिष्ट 1: विकासाधीन और संचालित कोयला ऊर्जा क्षमता की तालिका (मेगावाट) देश/क्षेत्रवार।

यह अनुवाद रिपोर्ट के केवल कुछ अंशों को शामिल करता है। रिपोर्ट का पूरा संस्करण [ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर](#) की वेबसाइट पर अंग्रेजी में उपलब्ध है।

ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर(GEM) के अलावा, इस रिपोर्ट के सह-लेखक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA), E3G, रिक्लेम फाइनैस, सिएरा क्लब, सोल्यूशंस फॉर आवर क्लाइमेट किको नेटवर्क, क्लाइमेट एक्शन नेट वर्क (CAN) यूरोप, वॉटरकीपर्स बांग्लादेश, धोरित्री रोखे आमरा(DHORA), ट्रेंड एशिया, पालिसी रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर एक्विटेबल डेवलपमेंट(PRIED), चिली सस्टेनेबिल, पोलन ट्रांससिसिएओनेस जस्टास, CEE बैंकवाच नेटवर्क, द इंस्टीट्यूट ऑफ लायर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट(INSAPROMA), अफ्रीका जस्ट ट्रांजीशन नेटवर्क(AJTN), एवं ARAYARA इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट हैं।

कार्यकारी सारांश

वर्ष 2024 में, कोयला ऊर्जा ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की: बीते बीस वर्षों में सबसे कम नई कोयला ऊर्जा क्षमता चालू हुई। यूरोपीय संघ (EU27) में बंद किए जाने वाले कोयला संयंत्रों की क्षमता चार गुना बढ़ी, जबकि यूनाइटेड किंगडम (UK) ने अपना अंतिम कोयला संयंत्र बंद कर दिया, जिससे वह 2015 के पेरिस जलवायु समझौते के तहत कोयला ऊर्जा को पूरी तरह समाप्त करने वाला छठा देश बना।

हालांकि, 2024 एक और महत्वपूर्ण बदलाव का वर्ष भी रहा, 2022-2023 के बाद चीन में कोयला संयंत्रों के निर्माण में पुनरुत्थान आने से नई परियोजनाओं में वृद्धि रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। वर्ष 2024 भारत के लिए भी नई कोयला संयंत्र परियोजनाएँ में विस्तार का वर्ष रहा। जब सरकार ने कई वर्षों की कठौती के बाद एक बार फिर कोयला आधारित ऊर्जा को बढ़ावा देने का समर्थन किया।

चीन और भारत को छोड़कर, दुनिया भर में कोयला ऊर्जा विकास की क्षमता लगातार दसवें वर्ष घट रही है। 2024 में केवल आठ देशों ने नए कोयला संयंत्रों का प्रस्ताव दिया, तथा 2023 से केवल 12 देशों ने इसका प्रस्ताव रखा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के 38 समृद्ध देशों में, कोयला संयंत्र प्रस्ताव 2015 में 142 से घटकर मात्र पाँच रह गए हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने 2040 तक कोयला ऊर्जा को समाप्त करने की घोषणा की है, जबकि मलेशिया सरकार ने 2044 तक इसे चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का संकल्प लिया है। लैटिन अमेरिका में, केवल ब्राजील में 0.1 गीगावाट का प्रस्तावित कोयला संयंत्र है और यह प्रस्तावित कोयला संयंत्र परियोजना वर्षों से रुका हुआ है।

हालांकि, OECD देशों में नए कोयला संयंत्र प्रस्ताव घट रहे हैं, लेकिन जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोयला संयंत्रों रद्द या बंद को करने की दर को तीन गुना बढ़ाना आवश्यक है, 2024 में सिर्फ 19 गीगावाट के कोयला संयंत्र बंद किए गए जिसको 2030 तक वार्षिक 70 गीगावाट क्षमता तक बढ़ने की जरूरत है। 200 गीगावाट से अधिक कोयला क्षमता पहले ही 40 वर्ष से अधिक पुरानी हो चुकी है, जोकि 37 वर्ष की औसत वैश्विक पुराने कोयला संयंत्रों को बंद किए जाने की आयु से अधिक है।

2024 की प्रमुख घटनाएँ

- 44 गीगावाट (GW) की क्षमता के साथ 2024, 2004 के बाद से, पिछले 20 वर्षों में नये कोयला विद्युत संयंत्रों का निर्माण निम्नतम स्तर पर रहा। चालू की गई क्षमता, 2004 से 2024 के लिए वार्षिक औसत (72 GW) से लगभग 30 GW कम थी।
- फिर भी, 44 गीगावाट की नई जोड़ी गई कोयला बिजली क्षमता 25.2 गीगावाट की रद्द या बंद की गई क्षमता से अधिक थी, जिसके कारण वैश्विक कोयला क्षमता में 18.8 गीगावाट की शुद्ध वृद्धि हुई। चीन के बाहर, कोयला बिजली क्षमता में 9.2 गीगावाट की कमी आई, क्योंकि रद्द या बंद की गयी क्षमता (22.8 गीगावाट), नई जोड़ी गई क्षमता (13.5 गीगावाट) से अधिक थी।
- यूरोपीय संघ में कोयला संयंत्र रद्द या बंद करे जाने की क्षमता चार गुना बढ़कर 2.7 GW से 11 GW हो गई, जिसमें जर्मनी ने 6.7 GW से अधिक संयंत्र बंद किए। UK ने अपना अंतिम कोयला संयंत्र बंद कर दिया, जिससे यह 2015 के पेरिस समझौते के बाद कोयला आधारित ऊर्जा को पूरी तरह समाप्त करने वाला छठा देश बन गया।
- अमेरिका में 2024 में रद्द या बंद की गई क्षमता घटकर 4.7 गीगावाट हो गई, जो 2015 के बाद सबसे कम थी। शेष अमेरिकी कोयला बिजली क्षमता का लगभग आधा हिस्सा 2035 तक रद्द या बंद होने की योजना के बावजूद पैसिफिकोर्प, इयूक एनर्जी और जॉर्जिया पावर इस नियोजित कोयला आधारित संयंत्रों को बंद करने में देर कर रहे हैं या इसे वापस ले रहे हैं।

- चीन और भारत के बाहर विकास के अंतर्गत कोयला विद्युत क्षमता में लगातार दसवें वर्ष कमी आयी है, जो 2015 में 445 गीगावाट से 80% से अधिक घटकर 2024 में 80 गीगावाट हो गई है। कोयला विद्युत क्षमता विकास में अब दस देशों की हिस्सेदारी 96% है।
- चीन में 94 GW नई कोयला ऊर्जा परियोजनाएँ शुरू हुईं, जो 2015 के बाद सबसे अधिक थीं। यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया, तो यह राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 2025 तक कोयला खपत को चरम पर पहुँचाने की प्रतिबद्धता को कमजोर कर सकता है।
- 2024 भारत में नए कोयला संयंत्र प्रस्तावों का भी एक रिकॉर्ड वर्ष था (38 गीगावाट), अकेले भारत और चीन 2024 में दुनिया भर में सभी नव प्रस्तावित कोयला बिजली क्षमता के 92% हिस्से (116 गीगावाट में से 107) के लिए जिम्मेदार हैं।
- इंडोनेशिया में प्रस्तावित कोयला क्षमता 2015 में 49.7 GW से घटकर 2024 में मात्र 4.9 GW रह गई है, जो 90% की गिरावट दर्शाती है। राष्ट्रपति प्रबोवो ने 2040 तक कोयला ऊर्जा को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का वादा किया है, हालांकि देश में नए कैप्टिव कोयला संयंत्रों के निर्माण के चलते इस लक्ष्य को साकार करने के लिए अभी भी महत्वपूर्ण योजना बनानी होगी।
- अफ्रीका में, जिम्बाब्वे और जाम्बिया में प्रस्तावित कोयला ऊर्जा क्षमता में वृद्धि हो रही है, जिनमें से अधिकांश परियोजनाएँ चीनी कंपनियों द्वारा प्रायोजित हैं, जबकि 2021 में इन सरकारों ने विदेशों में नए कोयला संयंत्रों के निर्माण को रोकने की प्रतिबद्धता जताई थी।
- दक्षिण पूर्व एशिया में कोयला संयंत्र प्रस्तावों में गिरावट देखी गई है, जो इंडोनेशिया और मलेशिया में कोयला क्षमता के चरणबद्ध समाप्ति की प्रतिबद्धताओं, फिलीपींस में कोयला संयंत्र स्वीकृति पर रोक, और वियतनाम में न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन योजना के विकास के कारण हुई है।
- लैटिन अमेरिका में कोयला संयंत्र प्रस्ताव लगभग शून्य हो गए हैं, केवल ब्राजील और होंडुरास में वर्षों से अटकी हुई परियोजनाएँ बची हैं। 2024 में, पनामा ने 2026 तक कोयला ऊर्जा को समाप्त करने की प्रतिबद्धता जताई थी।
- OECD के 38 समृद्ध देशों में, कोयला संयंत्र प्रस्ताव 2015 में 142 से घटकर अब मात्र पाँच रह गए हैं। फिर भी, अंतर्राष्ट्रीय पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वार्षिक कोयला सेवानिवृत्ति को तीन गुना बढ़ाकर 19 GW से 70 GW करना आवश्यक होगा।
- OECD देशों में कोयला चरणबद्ध समाप्ति में पिछड़ने वालों में जापान और कोरिया शामिल हैं, जो अपने कोयला संयंत्रों में महंगे और कम प्रभावी अमोनिया-फायरिंग तकनीक को बढ़ावा दे रहे हैं।

भारत: एक दशक में सबसे अधिक नये कोयला संयंत्र प्रस्तावित

भारत, 243 GW की संचालित कोयला क्षमता और 111 GW की निर्माणाधीन क्षमता के साथ, चीन के बाद वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा कोयला ऊर्जा उत्पादक देश है। भारत सरकार ने "[फ्रेज-डाउन](#)" का संकल्प लिया है, लेकिन इसे लागू करने की कोई औपचारिक समयसीमा तय नहीं की है। इसके बजाय, सरकार कोयले के विस्तार की योजना बना रही है, और कह रही है कि देश में कोयले का उपयोग संभवतः [2040 तक चरम पर नहीं होगा](#) - वह वर्ष जब आईईए के नेट जीरो परिदृश्य के अनुसार, पेरिस जलवायु समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को पूरा करने के लिए [वैश्विक स्तर](#) पर बेरोकटोक/नेट कोयला बिजली को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

भारत में 2010 के दशक की शुरुआत में कोयला संयंत्रों में निवेश [संकट](#) और [कम मांग](#) के कारण कोयला परियोजनाओं में भारी गिरावट आयी थी, जिससे [कई सौ गीगावाट](#) की परियोजनाएँ रद्द कर दी गई या निर्माण के दौरान ही [रोक दी गईं](#)। सरकार बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने को आवश्यकता का तर्क देते हुए, अब [फिर से](#) बड़े कोयला संयंत्रों के विकास को पुनः प्रोत्साहित कर रही है और [तेजी से](#) स्वीकृतियाँ दे रही है। इस बढ़ती मांग का एक प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ता तापमान और [बढ़ती कूलिंग आवश्यकता](#) भी है। अप्रैल 2024 की भीषण गर्मी के दौरान बिजली की वार्षिक मांग में 10% की वृद्धि हुई, जिसमें से [लगभग आधी वृद्धि](#) केवल कूलिंग की जरूरतों के कारण थी। ऊर्जा मंत्रालय ने 2024 में आयातित कोयले से चलने वाले संयंत्रों को अपनी अधिकतम क्षमता पर संचालित करने का [निर्देश](#) दिया, जिससे देश में कोयला ऊर्जा उत्पादन [रिकॉर्ड उच्च स्तर](#) पर पहुँच गया और इसने भारत के CO₂ उत्सर्जन को 1.2 बिलियन मीट्रिक टन के नए उच्च स्तर तक पहुँचा दिया। सरकार ने 2024 में 2032 तक 93 GW नई कोयला ऊर्जा क्षमता जोड़ने के लक्ष्य की निगरानी के लिए एक [पैनल](#) का गठन किया है।

नवीकरणीय ऊर्जा और कोयला ऊर्जा के बीच संतुलन

हालांकि भारत सरकार ने कोयला ऊर्जा के विस्तार का समर्थन किया है, लेकिन 2024 में [28.6 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता भी जोड़ी](#) गई, जो अब तक का सबसे अधिक वार्षिक क्षमता था। इसके बावजूद, भारत को 2030 तक [500 GW](#) गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वार्षिक नवीकरणीय ऊर्जा स्थापना दर को लगभग [दोगुना](#) करना होगा।

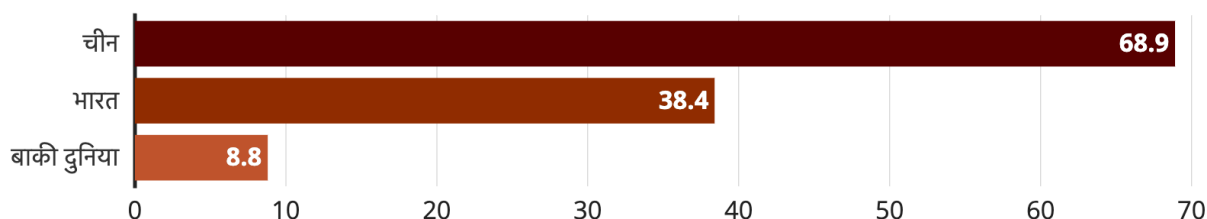
यदि 2024 में भारत ने सौर और पवन ऊर्जा क्षमता को 60 GW तक बढ़ाया होता, तो इससे उत्पन्न बिजली देश की [5.8%](#) बिजली मांग वृद्धि का 90% हिस्सा पूरा करने के लिए [पर्याप्त](#) होती- विशेष रूप से, पवन ऊर्जा का अधिक विकास ताकि गैर-सौर घंटों की बिजली मांग को पूरा किया जा सके। कौंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट, एंड वाटर (CEEW) की [2025 की एक रिपोर्ट](#) के अनुसार, यदि भारत अपने 2030 गैर-जीवाश्म लक्ष्य को पूरा करता है, तो सरकार की अनुमानित मांग बिजली मांग को पूरा करने के लिए नए कोयला संयंत्रों की आवश्यकता नहीं होगी।

आईईए की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बैटरी युक्त सौर पीवी, नए कोयला संयंत्रों के निर्माण की तुलना में सस्ता है, इसलिए देश के निवेश को कोयला ऊर्जा से सौर, पवन और बैटरी ऊर्जा में स्थानांतरित करने से देश को स्वच्छ ऊर्जा के साथ कम बिजली लागत पर अपने संपूर्ण लोड वृद्धि को पूरा करने में मदद मिल सकती है - और यह देखते हुए कि भारत में कोयला संयंत्रों को पहली बार चालू होने के प्रस्ताव के बाद औसतन [7 से 9 साल](#) लगते हैं, कोयले की तुलना में सौर, पवन और बैटरी ऊर्जा क्षमता अधिक तेजी से लगाई जा सकती है।

जब बात नए कोयला क्षमता प्रस्तावों की आती है, तो कोयले के लिए बढ़ते समर्थन ने भारत को चीन के बराबर ला खड़ा किया है, जबकि पिछले कई वर्षों से कोयला संयंत्रों के निरंतर विकास में चीन वैश्विक स्तर पर अकेला [अग्रणी](#) देश रहा है 2024 में, भारत और चीन मिलकर वैश्विक रूप से प्रस्तावित (116.1 गीगावाट) नई कोयला ऊर्जा क्षमता का 92% (107.3 GW) हिस्से के लिए जिम्मेदार थे (चित्र 28)। (चीन नए कोयला संयंत्रों का मुख्य प्रस्तावक बना होने के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा में भी वैश्विक नेता है, जिसने 2024 में भारत (28.6 गीगावाट) की तुलना में 13 गुना अधिक सौर और पवन ऊर्जा क्षमता (357 गीगावाट) को चालू किया है।)

2024 में प्रस्तावित सभी नए कोयला आधारित क्षमता में से 90% से अधिक में चीन और भारत का योगदान

2024 में प्रस्तावित कोयला आधारित क्षमता, गीगावाट (GW) में



स्रोत: ग्लोबल कोल प्लांट ट्रैकर, जनवरी 2025
इसमें नए प्रस्ताव और पुनः सक्रिय प्रस्ताव दोनों शामिल हैं



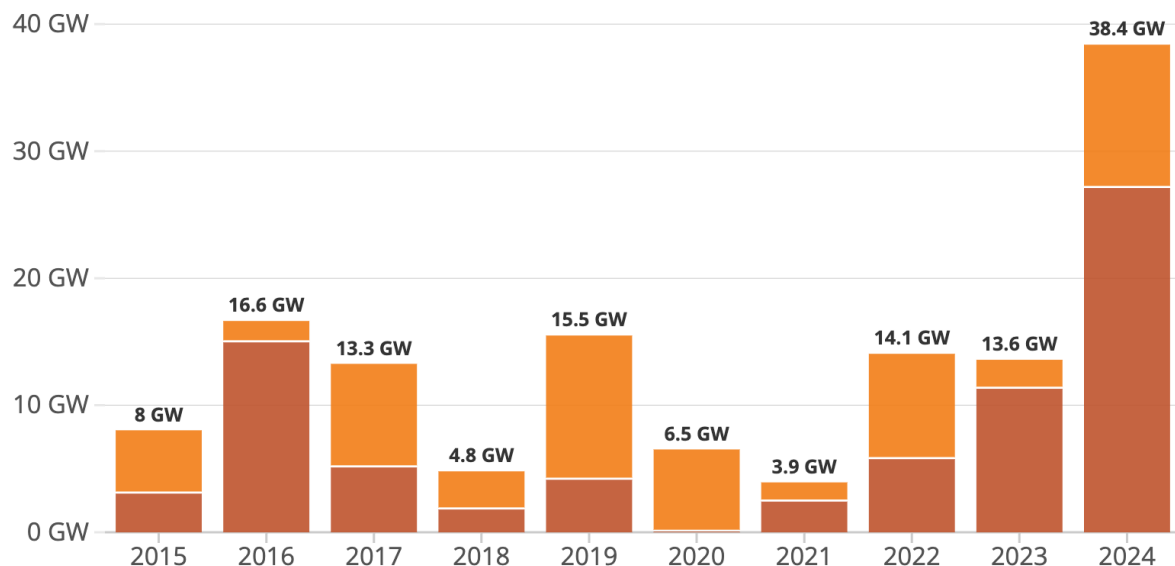
Figure 28

भारत अकेले 2024 में नए वैश्विक कोयला प्रस्तावों में से एक तिहाई के लिए जिम्मेदार है, जिसमें 27.2 गीगावाट के नए प्रस्ताव और 11.2 गीगावाट के पुनः सक्रिय प्रस्ताव शामिल हैं, जो कुल मिलाकर 38.4 गीगावाट है - कम से कम 2015 के बाद से नए कोयला संयंत्र प्रस्ताव 2024 में देश के लिए सबसे अधिक रहे (चित्र 29)। GEM के [वैश्विक ऊर्जा स्वामित्व ट्रैकर](#) के अनुसार, 38.4 गीगावाट के नए प्रस्तावों में से लगभग 60% (22.1 गीगावाट) सार्वजनिक धन का उपयोग करके राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं (SOE) द्वारा प्रायोजित हैं। 16.3 गीगावाट की नई प्रस्तावित गैर-SOE क्षमता में से, 60% (9.6 गीगावाट) भारत की [अडानी पावर](#) द्वारा प्रायोजित है, एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर भारत सरकार के शीर्ष सदस्यों के साथ घनिष्ठ संबंध होने के एवं कई भ्रष्टाचार के आरोप हैं। 38.4 गीगावाट के नए प्रस्तावों से भारत की कुल निर्माण-पूर्व कोयला संयंत्र क्षमता 2023 की तुलना में 75% बढ़कर 2024 में 81.4 गीगावाट हो गई है।

भारत में नए और पुनः सक्रिय कोयला प्रस्तावों ने रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ

नए प्रस्तावित कोयला बिजली क्षमता स्थिति और वर्ष के अनुसार, गीगावाट (GW) में

■ नए प्रस्तावित ■ पुनः सक्रिय प्रस्तावित



स्रोत: ग्लोबल कोल प्लांट ट्रैकर, जनवरी 2025

पुनः सक्रिय प्रस्तावों को स्थगित या रद्द कर दिया गया और फिर पुनः सक्रिय किया गया



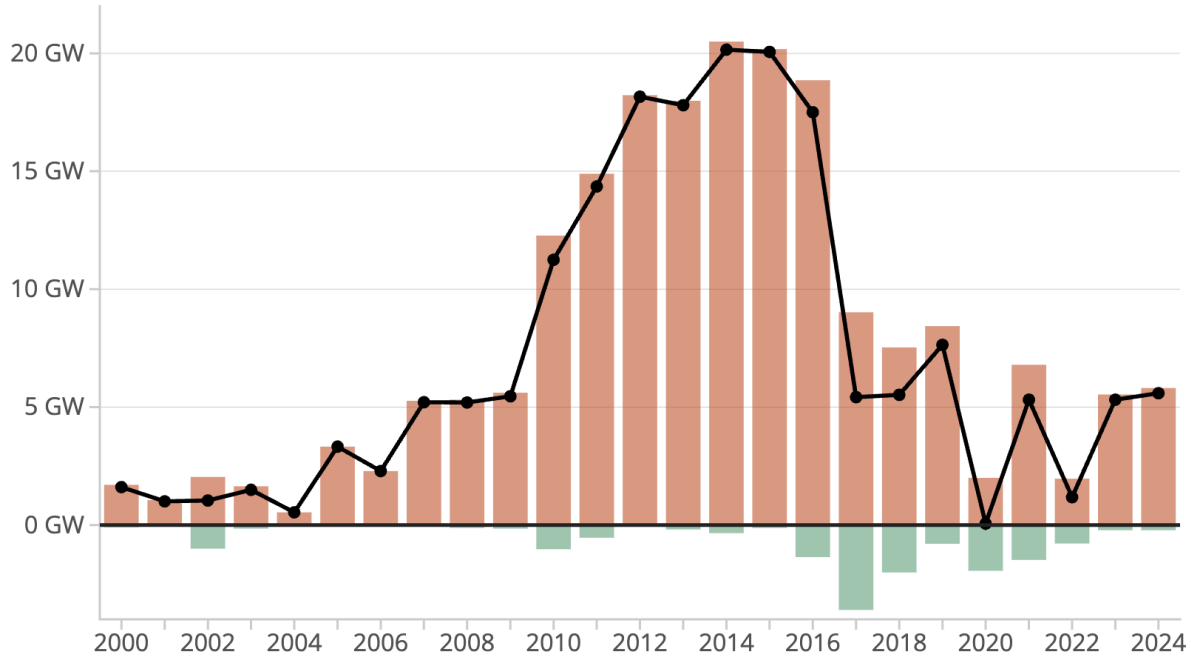
Figure 29

2024 में, भारत ने 5.8 गीगावाट की नई कोयला-संचालित क्षमता जोड़ी और 0.2 गीगावाट को बंद किया, जिससे क्षमता में 5.6 गीगावाट की शुद्ध वृद्धि हुई - जोकि 2019 के बाद से भारत के कोयला बेड़े में सबसे अधिक वृद्धि है (चित्र 30)। 2024 में, 2023 में बंद 0.2 गीगावाट के बराबर क्षमता को हो या रद्द या बंद किया गया, जो 2015 के बाद से सबसे कम बंद किए गए संयंत्रों की क्षमतारही। 2017 से 2022 तक पुरानी और रद्द किए गए कोयला संयंत्रों की क्षमता सीईए द्वारा मूल रूप से अनुमानित (23 गीगावाट में से 10 गीगावाट) के [आधे से भी कम](#) थी इसके बाद 2024 में बंद या रद्द किए जाने वाले कोयला बिजली संयंत्रों में गिरावट भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ([सीईए](#)) द्वारा 2023 के मार्गदर्शन के बाद आई है, जिसमें बिजली उपयोगिता कंपनियों को 2030 तक किसी भी थर्मल पावर इकाई को सेवानिवृत्त नहीं करने की सलाह दी गई है।

भारत में 2019 के बाद से कोयला क्षमता के संचालन में सबसे अधिक शुद्ध वृद्धि देखी गई है

कोयला आधारित बिजली क्षमता हर साल जोड़ी और हटाई जाने वाली क्षमता और शुद्ध परिवर्तन, गीगावाट (GW) में

■ शुद्ध परिवर्तन ■ जोड़ी गई ■ सेवानिवृत्त की गई



स्रोत: ग्लोबल कोल प्लांट ट्रैकर, जनवरी 2025



Figure 30

भारत में प्रदूषण नियंत्रण के बिना संचालित होने वाली पुरानी क्षमता की मात्रा को देखते हुए कम रद्द या बंद किए जाने वाले संयंत्रों की संख्या ध्यान देने योग्य है। 2015 में पारित [नियमों](#) के बावजूद, भारत में [केवल 8%](#) कोयला संयंत्रों में सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_x) को हटाने के लिए उपकरण हैं, ऐसा अदानी पावर सहित प्रमुख भारतीय बिजली कंपनियों के [भारी लॉबिंग दबाव](#) के बाद नियामक देरी के कारण हुआ है। इन प्रदूषकों के उत्सर्जन से महीन कण पदार्थ (PM_{2.5}/पी एम 2.5) बनते हैं, जो देश में [एयरपोकेलिप्स](#) धुंध की घटनाओं और हर साल अनुमानित [सौ हजार भारतीय](#) निवासियों की अकाल मृत्यु के कारक हैं। दिसंबर 2024 में, उत्सर्जन अनुपालन एक्सटेंशन/विस्तार की श्रृंखला के सबसे हालिया कदम में सभी ताप विद्युत संयंत्रों को उत्सर्जन कम करने के लिए [तीन साल की अतिरिक्त छूट](#) प्रदान की, और 2030 तक बंद होने वाले कोयला संयंत्रों के लिए SO₂ उत्सर्जन अनुपालन से पूर्ण छूट की पेशकश की गयी है – इसी वर्ष में सरकार ने कंपनियों को अपने कोयला संयंत्रों को चालू रखने के लिए प्रोत्साहित किया।

भारत ने अफ्रीका में भी नए कोयला ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा दिया है, विशेष रूप से कोयला-समृद्ध दक्षिणी देशों में, उदाहरण के लिए, जिम्बाब्वे में, जिंदल स्टील एंड पावर ने [हवांगे पावर स्टेशन](#) का 1.2 GW विस्तार करने की

योजना की घोषणा की, साथ ही 1980 के दशक के मध्य में निर्मित संयंत्र की छह मौजूदा इकाइयों के नवीनीकरण की भी योजना बनाई है। हवांगे में इन दो परियोजनाओं का कुल मूल्य 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया है, जोकि जिम्बाब्वे के इतिहास का सबसे बड़ा [एकल निवेश](#) बताया जा रहा है। जिंदल पड़ोसी देश बोत्सवाना में भी 0.6 GW [ममाबुला एनर्जी प्रोजेक्ट](#) के हाल ही में पुनर्जीवित और [विस्तारित प्रस्ताव](#) पर काम जारी रखे हुए है। जाम्बिया में, भारत की नवा लिमिटेड ने [माम्बा पावर स्टेशन](#) पर 0.3 GW विस्तार परियोजना का निर्माण शुरू किया, जिसे देश में सूखे के कारण उत्पन्न ऊर्जा संकट के बीच [तेजी से](#) स्वीकृति दी गई।